शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित और निर्धारित की जाती हैं। इसलिए इस मंत्रालय के लिए यह बताना संभव नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों के संबंध में स्कूलों में कोई भ्रष्टाचार विद्यमान है या नहीं।

(ख) और (ग). पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का संबंध राज्य सरकारों से है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है। तथापि, मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात को छोड़ कर बाकी सभी राज्य सरकारों ने विभिन्न स्तरों और भिन्न-भिन्न मात्राओं में पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

गांवों में डाकघर

1726. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि में गांवों में डाकघर खोलने के लिये कितनी जनसंख्या की सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे गांवों में, जहां हाई स्कूल और कालेज हैं, उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखकर डाकघर खोलने का है ;

(ग) क्या गांवों के डाकघरों पर व्यय उनकी आय के अनुपात से किया जाता है अथवा यह समान होता है ; और

(घ) गांव के प्रत्येक डाकघर पर औसतन वार्षिक व्यय कितना होता है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) डाकघर उन गांवों या दो मील की अरोय दूरी के भीतर आने वाले गांव-समूहों में, जिनकी आबादी 2000 या उससे अधिक हो खोला जाता है, बशर्ते कि मौजूदा डाकघर से उसकी दूरी तीन मील से कम न हो और घाटा प्रतिवर्ष 750 रु० से अधिक न हो। डाकघर उन गांव-समूहों में भी खोले जा सकते हैं जिनकी आबादी 2,000 से कम हो बशर्ते कि किसी मौजूदा डाकघर की दूरी तीन मील से कम न हो और घाटा प्रतिवर्ष 500 रु० से अधिक न हो। उन स्थानों के लिए जो सामुदायिक प्रायोजनाओं के मुख्यालय हों, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड हों या जहां जिला परिषद् या स्थानीय बोर्डों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल हों या ऐसे स्कूल हों जो राज्य सरकारों से स्वीकृत हों या जिन्हें उनसे सहायता मिलती हो, मौजूदा डाकघर से दूरी की सीमा की शर्त घटाकर 2 मील कर दी जाती है। उन क्षेत्रों में जिन्हें अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र घोषित किया गया हो, न्यूनतम आबादी की कोई पाबन्दी नहीं है। फिर भी आबादी या दूरी पर विचार किये बिना भी डाकघर खोले जा सकते हैं, बशर्ते कि उसमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी न लौटाये जाने वाला अनुदान देकर उसे चलाने पर होने वाला कुल खर्च वहन करने के लिए तैयार हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। दूसरी शर्तें पूरी होने पर डाकघर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि वार्षिक व्यय और आय में इतना अन्तर हो जो उस विशेष मामले पर लागू होने वाले घाटे का अनुमत्य सीमा के भीतर हो।

(घ) लगभग 1,000 रु०

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को मेरठ में बसाना

1727. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान